From the People of Japan
JICA
वर्ष-1: अंक-11
Vol-1: No.-11

द हिल कल्टीवेटर

Government of India

जुलाई, 2025
July, 2025

THE HILL CULTIVATOR

जायका कृषि परियोजना-2 की मासिक ई-पत्रिका • Monthly e-paper of HPCDP Project-II, JICA-ODA

प्राकृतिक खेती उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल

*अमित शाह ने हिमाचल में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की सराहना * राज्य का पहला प्राकृतिक कृषि क्षेत्र पांगी

नई दिल्ली: सहकारिता पर आयोजित 'मंथन बैठक' में हिमाचल प्रदेश आकर्षण का केंद्र रहा और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की पहल की सराहना की, जिसने देश के बाकी हिस्सों के लिए एक मिसाल कायम की है। इस बैठक में सभी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों ने भाग लिया।

जुलाई में नई दिल्ली में हुई सहकारिता 'मंथन बैठक' में अमित शाह ने कहा, 'हिमाचल में प्राकृतिक खेती में बहुत अच्छे प्रयोग हुए हैं।' उन्होंने हिमाचल प्रदेश द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि हिमाचल में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयोग सराहनीय हैं।

राज्य में हजारों किसान प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हिमाचल की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि, बागवानी और पशुपालन उनकी आजीविका का मुख्य आधार हैं।

इस बीच, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने कहा है कि राज्य में एक बढ़ता रुझान देखा गया है जहां किसान और बागवान प्राकृतिक खेती की ओर तेज़ी से आकर्षित हो रहे हैं। राज्य की लगभग सभी पंचायतों में 2,23,000 से ज़्यादा किसानों और बागवानों ने आंशिक या पूर्ण रूप से रसायन मुक्त खेती को अपनाया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के साथ, हिमाचल प्रदेश इस पद्धति से उगाई जाने

एक अन्य प्रमुख पहल में, राज्य सरकार ने चंबा जिले के पांगी उप-मंडल को राज्य का पहला प्राकृतिक कृषि उप-मंडल घोषित किया है, जिसका उद्देश्य दूरस्थ आदिवासी घाटी में पारंपरिक कृषि पद्धतियों को संरक्षित करना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है। किसानों ने प्राकृतिक कृषि तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया है क्योंकि वर्तमान में घाटी में लगभग 2,244 किसान परिवार सक्रिय रूप से रसायनमुक्त खेती कर रहे हैं।

वाली विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करके प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल मक्के के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया था जिसे अब बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। अब तक सरकार ने 1,509 किसानों से समर्थन मूल्य पर लगभग 400 मीट्रिक टन मक्का खरीदा है। इसी प्रकार, गेहूं की खरीद 60 रुपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। प्राकृतिक कृषि तकनीकों से उगाई गई कच्ची हल्दी पर 90 रुपये का न्यूनतम मूल्य दिया जाएगा, जिसे 'हिमाचल हल्दी' ब्रांड नाम से संसाधित और विपणन किया जाएगा। राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से 9.61 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

सरकार अब कृषि, बागवानी और अन्य कृषि क्षेत्रों को कवर करते हुए सभी 2,920 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि को 100 प्रतिशत प्राकृतिक खेती में बदलने की योजना बना रही है। इस कदम से घाटी के उन मेहनतकश किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त होंगे, जिन्हें पहले पांगी से बाहर रहते हुए खेती के लिए अपनी ज़मीन पट्टे पर देने के लिए मजबूर होना पड़ता था।

प्राकृतिक खेती के तहत उपज की बिक्री को सुगम बनाने के लिए, आवश्यक बुनियादी ढाँचे के साथ 10 मंडियों में निर्दिष्ट स्थान विकसित किए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में 27.60 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

दूध उत्पादकों ने परिवहन सब्सिडी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया

शिमला: कामधेनु हितकारी सोसाइटी से जुड़े दूध उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 17 जुलाई को यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने पंजीकृत दूध समितियों के लिए परिवहन सब्सिडी 1.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर तीन रुपये लीटर करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

इस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस वृद्धि से कामधेनु हितकारी सोसाइटी से जुड़े लगभग 6000 परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार, देश में दूध उत्पादकों को परिवहन सब्सिडी प्रदान करने वाली पहली सरकार है।

किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वे मुख्यमंत्री के आभारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कई पहल की हैं। हिमाचल प्रदेश दूध के लिए सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य बना है।

पशुपालकों से गाय का दूध 51 रुपये प्रति लीटर जबकि भैंस का दूध 61 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपनी आय बढ़ाने और आजीविका बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने का आग्रह किया है।

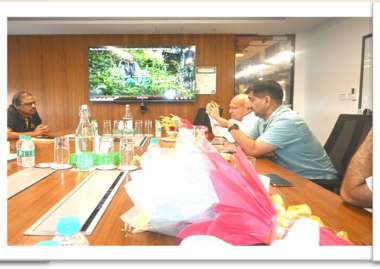

कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने किया दो राज्यों का दौरा

*कृषि व्यवसाय संचालकों के कारोबार का कर्नाटक, महाराष्ट्र में किया अध्ययन

हमीरपुर: माननीय कृषि मंत्री, हिमाचल प्रदेश प्रो. चंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया, उप मुख्य सचेतक, हिमाचल प्रदेश विधानसभा; डॉ. सुनील चौहान, परियोजना निदेशक, एचपीसीडीपी, जायका (चरण-II); डॉ. आशीष आनंद, विषय वाद विशेषज्ञ और डॉ. राकेश शर्मा, विषय वाद विशेषज्ञ, एचपीसीडीपी, जायका (चरण-II) थे। इस प्रतिनिधिमंडल ने 15 से 17 जुलाई, 2025 तक उपरोक्त राज्यों के विभिन्न कृषि व्यवसाय या एफपीओ संचालकों से मिलकर उनके कारोबार का अध्ययन किया। उस अनुभव को हिमाचल प्रदेश में कैसे अपने किसानों को लाभ दिलाया जा सके इसके बारे में भी उनसे चर्चा की।

इस दौरा का उद्देश्य था:- किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और कार्यप्रणाली, कृषि उपज के सामूहिक विपणन और ऑनलाइन विपणन रणनीतियों को समझना।

प्रतिनिधिमंडल के दौरे का उद्देश्य:-

इस प्रतिनिधिमंडल ने कृषि व्यवसाय से जुड़े कई पहलुओं पर व्यावहारिक जानकारी प्राप्त की।

* विभिन्न क्षेत्रों में एफपीओ/एफपीसी के कार्य मॉडल और सफलता का अध्ययन किया।

* कृषि उपज के सामूहिक विपणन और मूल्य संवर्धन के लिए अपनाई गई विपणन प्रणालियों को समझाना

* आपूर्ति श्रृंखलाओं और ई-मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म में तकनीकी एकीकरण को जानना

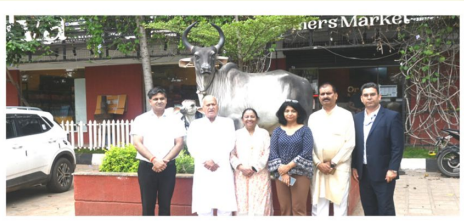

सतत कृषि के लिए जैविक खेती और मूल्य श्रृंखला विकास की जानकारी लेना।

प्रतिनिधिमंडल ने 15 जुलाई, 2025 को ऑर्गेनिक मांड्या, बैंगलोर का दौरा किया, जो जैविक कृषि और किसान सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला एक अनुकरणीय संगठन है।

प्रतिनिधिमंडल 16 जुलाई, 2025 को भारत के अग्रणी ऑनलाइन किराना प्लेटफार्मों में से एक, बिग बास्केट के बैंगलोर स्थित मुख्यालय का दौरा किया। बिग-बास्केट के प्रतिनिधियों ने अपनी वर्तमान प्रगति और भविष्य के दृष्टिकोण को समझाते हुए एक प्रस्तुति दी।

प्रतिनिधिमंडल 17 जुलाई, 2025 को एक सफल किसान उत्पादक कंपनी, सह्याद्रि फार्म्स, देखने नासिक, महाराष्ट्र पहुंचा। यह एफपीसी अपनी संपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला के लिए भारत में अग्रणी मॉडलों में से एक के रूप में उभरी है। सह्याद्रि फलों और सब्जियों के लिए भारत का सबसे बड़ा एकीकृत मंच है।

इस दौरे का निष्कर्ष:

यह अनुभव दौरा अत्यधिक ज्ञानवर्धक रहा। इस दौरे ने एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया कि किस प्रकार एफपीओ और कृषि उद्यम निम्नलिखित में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं:

* सामूहिक रूप से कार्य करना और पैमाने के माध्यम से किसानों की आय कम करना।

* मूल्य संवर्धन और जैविक खेती के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना।

*सामूहिक विपणन को बढ़ावा देकर, प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करके और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन विपणन को जोर कर, इन मॉडलों को से हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से दोहराया और अपनाया जा सकता है।

प्रतिनिधिमंडल ने जो सुझाव दिए हैं

को बढ़ाना।

* आपूर्ति श्रृंखला दक्षता और उत्पाद की पहचान में सुधार करना।

* प्रत्यक्ष बाजार संपर्क स्थापित करना और बिचौलियों पर निर्भरता वो यूँ हैं:

1. मौजूदा एफपीओ को मज़बूत बनाने के लिए ऐसे सफल मॉडलों के प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करना।

2. स्थानीय स्तर पर ग्रेडिंग, पैकेजिंग और मूल्यवर्धन के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास को सुगम बनाना।

3. पारंपरिक/प्राकृतिक कृषि समूहों को बढ़ावा देना और उन्हें जागरूक उपभोक्ता बाज़ारों से जोड़ना।

4. कृषि विपणन के लिए प्रौद्योगिकी और ई-कॉमर्स का लाभ उठाने हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

5. सफल प्रथाओं को प्रेरित करने और उन्हें दोहराने के लिए एफपीओ संचालकों और क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए इसी तरह के अनुभव दौरों का आयोजन करना।

प्रतिनिधिमंडल की यह अनुभव यात्रा अत्याधुनिक कृषि नवाचारों और सतत विकास पहलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मंच का कार्य करती है। सरकारी निकायों, स्टार्टअप्स और विकासात्मक संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, ऐसे प्रयास समावेशी विकास, पर्यावरण संरक्षण और जायका कृषि परियोजना-II में ग्रामीण कृषक समुदायों के समग्र-कल्याण को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

(पृष्ठ -4 पर)
*यात्रा का दिनवार विवरण

द हिल कल्टीवेटर
THE HILL CULTIVATOR

वर्ष-1: अंक-10 Vol-1: No.-10 | 2 | जुलाई, 2025 July, 2025

प्राकृतिक हल्दी से भट्टू में बना शुद्ध हल्दी पाउडर

हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना-II, जायका-ओडीए और राज्य परियोजना प्राकृतिक खेती के संयुक्त प्रयास से कांगड़ा जिला में भट्टू स्थित हल्दी प्रसंस्करण इकाई में 26 क्विंटल हल्दी से 4.60 क्विंटल शुद्ध हल्दी पाउडर तैयार किया गया। यह प्रसंस्करण कार्य भवारना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (FPC) द्वारा संचालित इकाई में सम्पन्न हुआ, जिसे हिमाचल प्रदेश जायका कृषि प्रोजेक्ट –II में इसके संचालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्राकृतिक खेती के द्वारा उत्पादित हल्दी, प्राथमिक धुलाई, वैज्ञानिक विधि से उबालना, छाया में सुखाना, मशीन द्वारा उच्च गुणवत्ता पिसाई, स्वच्छ व सुरक्षित पैकिंग और गाढ़े पीले रंग की, प्राकृतिक गंधयुक्त, कर्क्यूमिन युक्त शुद्ध हल्दी पाउडर।

किसानों को इस पहल के अंतर्गत प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से हल्दी की खरीद ₹90 प्रति

किलो की दर से की गई, जिससे उन्हें लागत से अधिक मूल्य प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन की जिम्मेदारी परियोजना और FPC द्वारा ली गई है, जिससे किसानों को बाजार तक पहुँच, मूल्य संवर्धन और उत्पाद की पहचान स्थापित करने में सहूलियत मिली है। प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार की दवाइयों और रसायनिक खादों का उपयोग नहीं होता है । हल्दी पाउडर की पैकिंग 'प्राकृतिक खेती राज्य परियोजना प्रमाणित' (SPNF Certified Naturally Grown) लेबल के साथ की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं में इसकी विश्वसनीयता और मांग में बढ़ोतरी होना तय है। यह पहल प्राकृतिक खेती को अपनाने वाले किसानों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ठोस कदम है। हिमाचल प्रदेश जायका कृषि परियोजना -II के परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान का कहना है कि यह पहल केवल हल्दी उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्यस्थानीय प्रसंस्करण और विपणन के माध्यम से किसानों की आय में दीर्घकालिक वृद्धि सुनिश्चित करना है। भवारना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से अन्य प्राकृतिक उत्पादों के प्रसंस्करण की संभावनाएं भी तलाश की जा रही हैं।

कोठी बटाला में लगाए हल्दी के प्रदर्शन

बिलासपुर: खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, बिलासपुर के अंतर्गत बहाव सिंचाई उपपरियोजना कोठी बटाला ज्योरा में लगभग 1,800 मीटर मुख्य कूहल और वितरण कूहल का सुधार व निर्माण किया गया, जिसमें लगभग 34.83 लाख रुपए का व्यय किया गया है। इस उप परियोजना का क्षेत्रफल लगभग 11.90 हैक्टर है और सिंचाई परियोजना से 65 किसान परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इस बार खरीफ मौसम में 7 किसानों ने हल्दी की प्रगति किस्म के प्रदर्शन जायका परियोजना के कृषि अधिकारियों की सहायता से 3.5 बीघा में (प्रति किसान आधा बीघा) हल्दी के प्रदर्शन प्लांट लगाए गए हैं। जायका प्रोजेक्ट के कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके, पंक्ति में बुवाई और मल्चिंग तकनीक किसानों को समझाई गई, किसानों को कृषि अधिकारियों द्वारा रोग प्रबंधन व कटाई के साथ-साथ इसके बिक्री के तरीकों पर भी मार्गदर्शन दिया गया। इन्हें प्राकृतिक खेती किसान के रूप में पंजीकृत किया गया है तथा हल्दी का उत्पादन इन प्रदर्शनों से 30 से 35 क्विंटल होने की अपेक्षा है।

सिंचाई योजना 'पधर' किसानों को समर्पित

*1100 मीटर 'खेत पहुंच मार्ग' भी बना

मंडी: हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना-II, जायका- ओडीए के अंतर्गत बनाई गई सिंचाई परियोजना पधर से आरंग का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरांत खण्ड परियोजना प्रबंधक इकाई मण्डी द्वारा सिंचाई परियोजना संम्बधित कृषक विकास समूह को 14 जुलाई, 2025 को हस्तांतरित की गई।

इस परियोजना के अंतर्गत हेड वियर के साथ-साथ सिंचाई के लिए 2000 मीटर जल वितरण पाइपों का भी उपयोग किया गया। इसके अलावा हाईड्रैंट चैम्बर व 500 मीटर एचडीपी पाइपों के द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाने का निर्माण किया गया। इस परियोजना में 13.63 हैक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की गई तथा इससे 47 किसान परिवार लाभांन्वित होंगे।

इस उप परियोजना के अंतर्गत किसानों को 1100 मीटर खेत पहुंच मार्ग का निर्माण भी किया गया है जिससे किसानों को अपनी उपज फसल नजदीकी बाजार या सब्जी मण्डी ले जाने के लिए सुविधा होगी।

इस उप परियोजना के निर्माण हेतु लगभग 1.08 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

इस समारोह में जिला परियोजना प्रबंधक, मण्डी डॉ. हेम राज वर्मा ने सिंचाई योजना के रख रखाव के बारे में जानकारी दी तथा किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए जागरूक किया।

खण्ड परियोजना प्रबंधक, मण्डी डॉ. राजेश जसवाल, डॉ. हंस राज कृषि विकास अधिकारी, शुभम मोदगील रूपांकन अभियन्ता, शैलेन्द्र निर्माण अभियन्ता और सौरव कनिष्ठ अभियन्ता भी उपस्थित रहें। हस्तांतरण के दौरान ग्राम पंचायत सनवाड़ के प्रधान श्रीमती मीरादेवी, कृषक विकास समूह के प्रधान श्री महेन्द्र पाल, प्रबंन्धक समिति के सदस्य तथाअन्य लाभार्थी किसान उपस्थित थे।

कृषक विकास समूह के प्रधान श्री महेन्द्र पाल ने जायका परियोजना का धन्यवाद करते हुए विश्वास दिलाया की जो परियोजना की ओर से मार्ग दर्शन होगा उसको इस कुहल से लाभांन्वित किसान पूरा करेंगे और अपनी आर्थिकी को मजबूत करेंगे।

कृषि मशीनरी पर पोर्टल सक्रिय

किसानों को आधुनिक मशीनरी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा एग्री मशीनरी वेब-पोर्टल- https://agrimachinery.nic.in- 18 जुलाई, 2025 से सक्रिय हो गया है। इसके माध्यम से प्रदेश के किसान विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर अनुदान हेतु आवेदन कर सकेंगे।

कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कृषि कार्यों के मशीनीकरण से किसानों की कार्यक्षमता एवं आमदनी बढ़ती है, लागत में कमी आती है और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होता है।

कृषि विभाग का उद्देश्य किसानों को नई, आधुनिक और उन्नत किस्म की कृषि मशीनरी व उपकरण उपलब्ध करवाना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और छोटे खेतों को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों के अनुकूल कृषि यंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिल्लर, पावर वीडर और अन्य कृषि उपकरण इस पोर्टल के माध्यम से अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया है। प्रवक्ता ने किसानों से आग्रह किया कि वे केवल केंद्र सरकार से पंजीकृत फर्मों तथा स्वीकृत मॉडल की मशीनरी की खरीद करें और इस पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। कृषि विभाग का उद्देश्य आधुनिक मशीनरी से किसानों की आय बढ़ाना है।

दवाड़ में फूलगोभी की नर्सरी उगाने का प्रदर्शन

देहरा: हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना-II के अंतर्गत बहाव सिंचाई परियोजना दवाड़ में स्वस्थ नर्सरी उगाने पर 15 जुलाई को एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, देहरा द्वारा किया गया, जिसमें परियोजना टीम ने स्थानीय किसानों को सिखलाई दी।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फूलगोभी की मेघा" किस्म की नर्सरी की बुआई को प्रोट्रे (Pro Tray) पद्धति से प्रदर्शित करना था। यह पद्धति वैज्ञानिक व उन्नत खेती के अंतर्गत आती है, जिसमें पौधों की प्रारंभिक अवस्था को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रदर्शन के अंतर्गत प्रमाणित बीजों को निष्क्रिय माध्यम जैसे कोको पीट, वर्मी कम्पोस्ट आदि से भरी प्रो ट्रे में बोया गया, जिससे अंकुरण दर बढ़े और रोपाई के समय पौधे स्वस्थ रहें। इस तकनीकी प्रदर्शन के दौरान विस्तार अधिकारियों ने किसानों को प्रो ट्रे नर्सरी पद्धति के प्रमुख लाभों से अवगत कराया, जैसे: फसल की एकरूपता व मजबूती, रोग रहित पौध तैयार करना, जल, समय एवं श्रम की बचत, बेहतर जड़ विकास व रोपाई में सफलता, उत्पादन में वृद्धि की संभावना। किसानों ने इस नई तकनीक में गहरी रुचि दिखाई तथा इसे पारंपरिक विधियों की तुलना में अधिक उपयोगी और व्यावसायिक दृष्टि से लाभकारी बताया।

इस पहल का उद्देश्य किसानों को स्वस्थ पौध तैयार करने की वैज्ञानिक विधियों से जोड़ना था, जिससे वे न केवल अपनी उपज की गुणवत्ता सुधार सकें, बल्कि खेती को व्यावसायिक रूप में विकसित कर अपनीआय में स्थायी वृद्धिभी कर सकें।

यह प्रशिक्षण तकनीकी सशक्तिकरण एवं नवाचार आधारित खेती की ओर प्रोत्साहित करने के क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। ऐसे प्रदर्शन क्षेत्रीय किसानों को जलवायु अनुकूल, गुणवत्ता युक्त और बाजारोन्मुख कृषि अपनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे।

35 सामुदायिक प्रेरकों को दिया गया प्रशिक्षण

पालमपुर: हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना-II के अंतर्गत चयनित सामुदायिक प्रेरकों के लिए तीन दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 28 से 30 जुलाई 2025 तक चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में किया गया। इस प्रशिक्षण में खंड परियोजना प्रबंधन, इकाई पालमपुर, देहरा और धर्मशाला के अंतर्गत 18 सिंचाई उप-परियोजनाओं से आए 35 प्रेरकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रेरकों को संस्थागत विकास, प्राकृतिक खेती, सिंचाई प्रबंधन और परियोजना निगरानी से जुड़ी बारीकियों से अवगत कराना था।

प्रशिक्षण के पहले दिन जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई पालमपुर से डॉ. रजनीश शर्मा, विषय वाद विशेषज्ञ ने हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना-II की रूपरेखा, लक्ष्यों और सामुदायिक प्रेरकों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से जानकारी दी। तत्पश्चात डॉ. लव भूषण, डॉ. जी.डी. शर्मा और डॉ. रविंद्र सिंह, द्वारा हिमाचल में फसल विविधिकरण की संभावनाओं, आवश्यकता और वैज्ञानिक पद्धतियों पर व्याख्यान प्रस्तुत किए। दूसरे दिन परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के विशेषज्ञ डॉ. आर.के. शर्मा एवं डॉ. पी.एल. शर्मा ने कृषक विकास संघ, स्वयं सहायता समूह, वस्तु आधारित समूह जैसे संस्थागत ढांचों की संरचना, सशक्तिकरण और संचालन की प्रक्रिया पर गहन चर्चा की। साथ ही, सिंचाई प्रबंधन, विविध फसली उपकरण, डेटा संकलन तकनीक और निगरानी पत्रकों के उपयोग की जानकारी दी गई।

प्रतिभागियों को प्रायोगिक ज्ञान प्रदान करने हेतु पालमपुर, कृषि विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, कृषि संग्रहालय और विश्वविद्यालय के अनुसंधान खेतों का भ्रमण कराया गया। जिला परियोजना प्रबंधक डॉ. योगेन्द्र पॉल कौशल, पालमपुर ने कहा कि ये प्रशिक्षित मोटिवेटर्स अपने-अपने उप-परियोजना क्षेत्रों में किसानों को जागरूक करने, समूह गठन, महिला सशक्तिकरण तथा आजीविका विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

जायका की सिंचाई योजना से समखेतर में आई हरियाली

मंडी: जोगिंदर नगर उपमंडल की ग्राम पंचायत बुल्हा भड़याड़ा के समखेतर गांव में वर्षों से सूखे पड़े बंजर खेतों में अब लहराती फसलें देखकर किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। यह बदलाव संभव हुआ है। जायका द्वारा 39.47 लाख रुपये की लागत से निर्मित बहाव सिंचाई परियोजना के माध्यम से यह संभव हो पाया है।

इस उप-परियोजना के तहत, भेड़े नाला से पानी को पाइपलाइन व पक्की नालियों और अन्य संरचनात्मक उपायों के जरिये खेतों तक पहुंचाया गया, जिससे पहले जो जमीन बंजर हो चुकी थी, वह अब दोबारा कृषि योग्य बन गई है। किसानों के अनुसार, अब वे वर्ष में दो फसलें उगाने में सक्षम हो गए हैं. पहले जहां सिर्फ वर्षा पर निर्भरता थी, वहीं अब सिंचाई की सुविधा ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया है। समखेतर गांव के एक किसान शीला देवी ने बताया कि पहले हमारे खेत 10-12 साल से बंजर हो चुके थे, सिंचाई का कोई साधन नहीं था। अब इस परियोजना से खेतों में नमी बनी रहती है और हम गेहूं, मक्की व सब्जियां भी उगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें जायका कृषि परियोजना द्वारा अदरक व हल्दी के बीज भी प्रदान गए हैं जिससे जंगली जानवरों की डर से बंजर पड़ी भूमि दोबारा उपजाऊ हों पायी है। इस फसल के तैयार होने पर जाइका द्वारा ही इसे खरीदा जाना है। इससे न केवल किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी बल्कि परियोजना द्वारा घरद्वार में ही बाज़ार उपलब्ध करवाया जा रहा है। ग्राम प्रधान भीम सिंह ने बताया कि जाइका की इस परियोजना ने गांव की कृषि व्यवस्था को एक नई दिशा दी है। युवाओं में भी खेती को लेकर उत्साह बढ़ा है और प्रवास की प्रवृत्ति में कमी आई है।

खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, सरकाघाट ने ग्रामीणों को समय-समय पर तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान किया, जिससे वे पानी का कुशल प्रबंधन कर सकें।

इस बारे एसएमएस अश्वनी कुमार ने बताया कि इस उप-परियोजना से लगभग 12.80 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है, जिसमें लगभग 70 किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस सिंचाई परियोजना को समयबद्ध पूरा किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके अलावा जाइका द्वारा किसानों को अदरक व हल्दी के मुफ्त बीज प्रदान किए गए हैं, जिसको जायका द्वारा सीधे किसानों से खरीदा जाना है।

समखेतर गांव की यह कहानी बताती है कि यदि योजनाएं सही तरीके से धरातल पर उतारी जाएं, तो सूखा और बंजरपन भी हरियाली में बदला जा सकता है। जायका कृषि परियोजना की यह सिंचाई परियोजना न सिर्फ तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गई है।

लोहारा में 'मिट्टी रहित' पौध उगाने का प्रशिक्षण

मंडी: खण्ड परियोजना प्रबंधक इकाई, मण्डी के द्वारा बनाई जा रही सिंचाई उप परियोजना (शैलो ट्यूबवेल) लोहारा में 19 जुलाई 2025 को मिट्टी रहित माध्यम द्वारा अगेती फूलगोभी की पौध तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया।

इस प्रशिक्षण में 35 किसानों सहित खण्ड परियोजना प्रबंधक इकाई मण्डी, सरकाघाट और कुल्लू के प्रसार अधिकारियों ने भी भाग लिया।

इस प्रशिक्षण समारोह में खण्ड परियोजना प्रबंधक, मण्डी डॉ. राजेश जसवाल ने बताया कि इस परियोजना में लगभग 10.7 हैक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है तथा इससे 37 किसान परिवार लाभांन्वित होंगे।

डॉ. राजेश जसवाल ने बताया कि कोकोपीट और जैविक खाद से तैयार किए जाने वाली पौध से लगभग 0.5 हैक्टेयर क्षेत्र में अगेती फूलगोभी की फसल तैयार की जाएगी।

इस तकनीक से तैयार की गई पौध में बीमारी और कीट लगने की संभावना काफी कम हो जाती है तथा बीज की मात्रा भी कम लगती है।

इसमें डॉ. हंस राज कृषि विकास अधिकारी व उप प्रधान ग्राम पंचायत लोहारा तथा कृषक विकास संघ के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

प्राकृतिक खेती से किसान खुशहाल : सुरक्षित भोजन से उपभोक्ता निहाल

द हिल कल्टीवेटर
THE HILL CULTIVATOR
वर्ष-1, अंक-10 Vol-1: No-10 3 जुलाई, 2025 July, 2025

प्राकृतिक खेती और कृषि कारोबार की नीतियों पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा प्रोजेक्ट

प्राकृतिक खेती के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला पहला राज्य बनने पर प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-II, जायका-ओडीए की ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार, किसान और सभी हितकारकों को बधाई। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार और कृषि सचिव डॉ. सी. पॉलरासु के सुयोग्य मार्गदर्शन को श्रेय जाता है। इस पहल की केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हिमाचल में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।

केवल यहीं नहीं, मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग प्रशासन पर विश्वास जगाते हुए पांगी उपमंडल, राज्य का पहला प्राकृतिक कृषि क्षेत्र अधिसूचित करके इस क्षेत्र के किसान परिवारों के सशक्तिकरण की पहल भी की है, जिससे पांगी के लोग सरकार इस फैसले से खुश हैं। हिमाचल प्रदेश जायका कृषि परियोजना-II, परियोजना क्षेत्र में भी प्राकृतिक खेती को लोकप्रिय बनाने और सरकार की इस पहल में पूरा योगदान दिया जा रहा है और प्राकृतिक खेती से उगाई हल्दी का पाउडर बनाने के लिए परियोजना के भट्ठ स्थित किसान उत्पादक संस्थान ने योगदान दिया है। हमने ई-पत्रिका के माध्यम से प्रदेश सरकार की इस पहल को गांव तक पहुँचाने की कोशिश की है।

उन्नत खेती और प्राकृतिक खेती से किसानों को ज्यादा मदद हो सके और प्रदेश से बाहर अच्छे दाम मिल सके. इसके लिए कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक, महाराष्ट्र में कृषि करोबार का भ्रमण किया। प्रतिनिधिमंडल ने बैंगलोर में 'बिग-बास्केट' महाराष्ट्र के नासिक में सह्याद्री फार्म्स करोबार का अध्ययन किया गया, जो कि प्रदेश सरकार की स्थापित अगामी कृषि विपणन रणनीति बनाने में कारगर सिद्ध हो सकती है। इस बारे में हमने ई-पत्रिका के माध्यम से विस्तृत रिपोर्ट भी सभी हितधारकों से साँझा की है। सरकार द्वारा रियायति मूल्यों में कृषि मशीनरी किस तरह से मिल सकती है, इसे लेकर भी कृषि मशीनरी पोर्टल के शुरू होने की जानकारी अपने पाठकों तक पंहुचाई है।

जायका कृषि परियोजना-II में और नए कार्य कौन कौन से चल रहे हैं, हमने ई-पत्रिका में इनकी प्रमुख जानकारी दी है। उच्च कृषि तकनीकों जैसे, हाइड्रोपोनिक्स इकाइयां या उच्च गुणवत्ता के पॉली-हाउस स्थापित करने के लिए किये जा रहे हैं प्रयासों को उजागर किया है। कृषि विज्ञान केंद्र, बड़ा के उत्कृष्टता केंद्र में उन्नत तकनीक से तैयार सब्जियों की स्वस्थ्य पौध की तकनिकी भी किसानों को दिखाई जा रही है। परियोजना के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसान संवाद कार्यक्रम में जाएं, इस पर मैं स्वयं भी अमल कर रहा हूं. अधिकारी किसानों से सीधा संपर्क बनाएं जिससे उनकी समस्याओं का समाधान भी साथ-साथ किया जा सके। परियोजना के प्रशिक्षण अयोजित करने और प्रदर्शन प्लॉट्स लगाने के कार्यक्रम नियम के अनुसार किये जा रहे हैं।

जायका कृषि परियोजना-II की मासिक समीक्षा बैठकों में परियोजना कार्यों में जो कमियां दिखती हैं, उन्हें दूर करने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। परियोजना के स्टाफ ने किसान परिवारों के सहयोग से जो कार्य तेजी से आगे बढ़ायें हैं, उसके लिए मैं परियोजना प्रबंधक की ओर से उनको बधाई देता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि जो परियोजना कार्य इस वर्ष निर्धारित किये हैं उनको पूरा करने के बाद हम खुद अपने कार्यों का मूल्यांकन करेंगे और अगले वर्ष में और तेजी से काम करेंगे। इस अवधि में कृषि उत्पादन, मूल्य निर्धारण और कृषि-व्यापार की गतिविधियों को मजबूत बनाते हुए किसान परिवार को खुशहाल बनाने के लिए अनुकर्णीय मॉडल और मानक स्थापित करेंगे।

-डॉ सुनील चौहान ,
प्रधान सम्पादक एवं
परियोजना निदेशक

गोहर के किसान संवाद कार्यक्रम में डॉ. सुनील चौहान

*** कंसा खड्ड-पलोटा में खेतों का किया दौरा *सहकारी बैंक के निदेशक श्री लाल सिंह कौशल भी हुए शामिल**

मण्डी: जायका कृषि परियोजना के परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने 30 जुलाई, 2025 को कंसा खड्ड-पलोटा में खेतों का दौरा किया और किसान संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस कार्यक्रम में सहकारी बैंक के निदेशक श्री लाल सिंह कौशल ने भी भाग लिया। इन कार्यक्रमों का आयोजन खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, गोहर ने किया।

परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने किसानों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के प्रयासों की प्रशंसा की। स्थानीय ग्राम के प्रधान ने डॉ. सुनील चौहान और श्री लाल सिंह कौशल का अभिनंदन किया।

डॉ. सुनील चौहान ने प्रगतिशील किसानों, श्री डोला राम, श्री तीर्थराज, श्री संजय सकलानी, श्री चिंत राम, श्री नारायण दास और श्री जितेंद्र कुमार का उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया साथ में कृष्ण स्वयं सहायता समूह, कंसा खड्ड-प्लाहोटा और शिव स्वयं सहायता समूह, गवार-मसावरी को भी उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया।

दौरे की शुरुआत लाल चावल के एक प्रदर्शन प्लाट के निरीक्षण से हुई, इस प्रदर्शन प्लाट में एचपीआर-2795 किस्म लगाई गई है, ये प्रदर्शन प्लाट 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगाया गया है। इसके साथ ही 500 वर्ग मीटर के एक पॉलीहाउस में शिमला मिर्च की किस्म पलाडिन को ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग शीट का उपयोग किया गया है और इसकी पौध उत्कृष्टता का केंद्र बड़ा से ली थी। सभी गणमान्यों को मिट्टी रहित कल्चर का उपयोग करके प्रोट्रे में फूलगोभी किस्म मेघा की पौध का अवलोकन भी करवाया गया।

इसके उपरांत 800 वर्ग मीटर खुले क्षेत्र में उगाई गई शिमला मिर्च के खेतों का निरीक्षण भी करवाया गया। जहां तुलनात्मक प्रदर्शन के रूप में ड्रिप और मल्चिंग का उपयोग करके उसी किस्म (पलाडिन) की खेती की गई। उन्होंने एक संकर चावल (किस्म: यूएस 312) की फसल को भी देखा, जिसकी खेती 400 वर्ग मीटर भूमि पर की गई थी।

इस कार्यक्रम में एक कृत्रिम इंटेलिजेंस (एआई)-आधारित मृदा नमी सेंसर का भी प्रदर्शन किया गया। इस सेंसर द्वारा यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि वर्तमान मृदा नमी के स्तर के आधार पर सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं।

डॉ. सुनील चौहान की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, गोहर के प्रयासों की सराहना की और उन्नत कृषि पद्धतियों के प्रसार को प्रोत्साहित किया। उन्होंने जल उपयोग दक्षता में वृद्धि, उपज में वृद्धि और खरपतवार रोकथम उपायों पर ज़ोर दिया। परियोजना निदेशक ने सब्जी उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को मज़बूत करने में किसानों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के योगदान की भी सराहना की।

परियोजना की पीएमसी विशेषज्ञ डॉ. आर.के. शर्मा ने आगामी फसल मौसम के लिए पहले से ही एक योजना तैयार करने की सलाह दी, जिसमें बेहतर उत्पादकता और स्थिरता के लिए उपयुक्त फसल विकल्प और तकनीकी हस्तक्षेप शामिल हों। इस कार्यक्रम में पीएमसी विषयवाद विशेषज्ञ डॉ. खूब राम ठाकुर, डीपीएमयू मंडी और वीपीएमयू गोहर के अधिकारी भी शामिल हुए।

****

हाइड्रोपोनिक्स इकाइयां लगाने के लिए अध्ययन करेगी हिमाचल प्रदेश जायका कृषि परियोजना: डॉ. सुनील चौहान

हमीरपुर: जायका कृषि परियोजना हिमाचल प्रदेश में ईकी फार्म्स (EEKI Farms) के सहयोग और प्रगतिशील किसानों की भागीदारी से एक से दो एकड़ की हाइड्रोपोनिक्स इकाइयां स्थापित करने की संभावनाओं का अध्ययन कर रही है ये निर्णय हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2, जायका-ओडीए, के साथ ईकी फार्म्सके प्रतिनिधियों की "मूल्य श्रृंखला और बाजार विकास" कॉम्पोनेन्ट के अंतर्गत संभावित साझेदारियों पर 22 जुलाई, 2025 चर्चा हुई। इस बैठक की अध्यक्षता परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने की. बैठक में ईकी फार्म्स ने प्रस्तुत नवीन खेती और विपणन मॉडलों का उल्लेख किया जिसमें टिकाऊ कृषि पद्धतियों, बाजार संबंधों और किसानों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

ईकी-फार्म्स के प्रतिनिधि पंकज कौल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि EEKI का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए पारंपरिक कृषि को, एक अधिक पूर्वानुमानित, लाभदायक और कृषिटिकाऊ उद्यम में बदलना है। उन्होंने उत्पादकता में वृद्धि, जल और उर्वरक उपयोग दक्षता और किसानों की आय में वृद्धि को दर्शाने वाले कार्यों पर प्रकाश डाला। इस बात पर भी चर्चा की गई कि संस्था कम लागत पर उच्च उत्पादकता प्राप्त करने में किसानों की सहायता के लिए पेटेंट प्राप्त तकनीकों, डेटा-संचालित प्रथाओं और वास्तविक देखरेख करके नवीन प्रणालियों का लाभ दिलाती है। EEKI फार्म्स, विश्व की अच्छी कृषि उत्पादन प्रणाली (Global GAP) के लिए प्रमाणित है और ये संस्था किसानों से उपज की सुनिश्चित खरीद करती है।

इस बैठक में कुछ मॉडलों और सेवाओं को विस्तार से प्रस्तुत किया गया जैसे :-

(क) हाइड्रोपोनिक खेती तकनीक: हाइड्रोपोनिक्स को एक मृदा-रहित, उच्च-दक्षता वाली खेती तकनीक से पौधे पोषक तत्वों वाले पानी में पॉलीहाउस जैसे नियंत्रित वातावरण में उगाये जाते हैं। टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, लेट्यूस, पालक और अन्य पत्तेदार सब्जियों और बेल वाली फसलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों का साल भर उत्पादन संभव है।हाइड्रोपोनिक प्रणाली के तहत किसानों के साथ सहयोग के लिए दो मॉडल साझा किए:-

* मॉडल 1: सीधी खरीद - इस मॉडल के तहत, किसान स्वतंत्र रूप से हाइड्रोपोनिक इकाई खरीदता है और ईकी फार्म्स से निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करके इकाई का संचालन व प्रबंधन करता है। इसके अतिरिक्त, बाजार से जुड़ाव और आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक औपचारिक उत्पादन खरीद का समझौता भी किया जाता है।

* मॉडल 2: ईकी फार्म्स 60:40 के आधार पर राजस्व साझा करते हुए खेती और विपणन सहित पूरी इकाई का प्रबंधन करेगा।

ख) उच्च तकनीक पॉलीहाउस खेती:इस बात पर ज़ोर दिया गया कि ईकी फार्म्स ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन इकाइयों के साथ एकीकृत अनुकूलित पॉलीहाउस डिज़ाइनों का समर्थन करता है। यह प्रणाली सब्जियों की संरक्षित खेती के लिए आदर्श है और इसे क्षेत्रीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाया जा सकता है।इसके अलावा, ईकी फार्म्स फसल-विशिष्ट अभ्यास पैकेज, तकनीकी सहायता और कृषि निगरानी प्रदान करता है ताकि उत्पादकता और गुणवत्ता मानकों को लगातार पूरा किया जा सके।

ग) किसान-केंद्रित विपणन मॉडल: ईकी फार्म्स एक एकीकृत विपणन और खरीद मॉडल प्रदान करके बाज़ार पहुँच की महत्वपूर्ण चुनौती का समाधान करते हैं, जिसमें किसान उपज का थोक एकत्रीकरण, बाज़ार में आकर्षण बढ़ाने के लिए प्रमाणित मानकों के तहत ब्रांडिंग शामिल है।

प्रदर्शन स्थलों के लिए प्रस्ताव - ज़िला हमीरपुर:

परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने सुझाव दिया कि ज़िला हमीरपुर के नादौन निर्वाचन क्षेत्र को हाइड्रोपोनिक तकनीक के प्रायोगिक परीक्षण के लिए प्रगतिशील किसानों को शामिल करकेएक प्रदर्शन स्थल के रूप में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है,ताकि बड़े कृषक समुदाय के बीच इसके लाभों और परिचालन व्यवहार्यता को प्रदर्शित किया जा सके।इस उद्देश्य के लिए हमीरपुर जिले में 4 से 5 क्लस्टर और प्रत्येक क्लस्टर में एक एकड़ क्षेत्रफल वाले किसानों की पहचान और विकास करने का भी निर्णय लिया गया।

परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसी मूल्यवर्धन गतिविधियों के लिए हमीरपुर जिले के सायरा स्थित पैक हाउस सुविधा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसका उद्देश्य बाजार की तैयारी को बढ़ाना और समग्र विपणन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना है।

इस बात पर भी चर्चा हुई कि लाहौल-स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी सहित पड़ोसी जिलों से फलों और सब्जियों को सायरा पैक हाउस में एकत्रित किया जा सकता है ताकि पूरे क्षेत्र में सामूहिक विपणन और कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन संभव हो सके।

परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने निर्देश दिए कि हिमाचल प्रदेश के कृषि परिदृश्य के संदर्भ में प्रस्तावित मॉडलों की तकनीकी व्यवहार्यता और परिचालन उपयुक्तता का आकलन करने के लिए ईकी फार्म्स और प्रदर्शन स्थलों का क्षेत्रीय दौरा आयोजित किया जायेगा।

इसके साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) और परियोजना प्रबंधन सलाहकार इकाई (PMC) की टीमें EEKI फार्म्स के साथ मिलकर एक विस्तृत और व्यापक प्रस्ताव तैयार करेंगी जिसमें तकनीकी, वित्तीय (अर्थात् वित्तपोषण तंत्र, विशेष रूप से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)) और डीओए फार्म्स पर पायलट कार्यान्वयन के लिए अभिसरण रणनीतियों को शामिल किया जाएगा।

परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने और आधुनिक कृषि-प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ तालमेल बैठने के महत्व पर भी ज़ोर दिया।

बैठक समन्वित प्रयासों के माध्यम से कृषि परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, सहयोगात्मक रूप से मापनीय और टिकाऊ कृषि मॉडल विकसित करने की आपसी समझ के साथ संपन्न हुई। इस मौके में डॉ. राजेश, उप-परियोजना निदेशक (एम एंड पी एच), नितिका, वरिष्ठ विपणन अधिकारी के अतिरिक्त परियोजना प्रबंधन परामर्श इकाई -PMC, के विशेषज्ञ भी शामिल हुये।

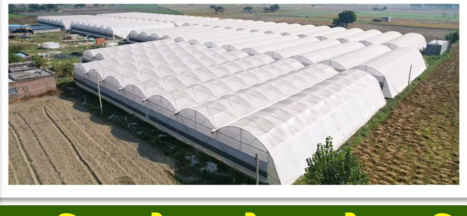

प्राकृतिक खेती से किसान खुशहाल : सुरक्षित भोजन से उपभोक्ता निहाल

द हिल कल्टीवेटर
THE HILL CULTIVATOR

वर्ष-1, अंक-10 Vol-1: No.-10: 4 जुलाई, 2025 July, 2025

प्रो. चंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने किया कृषि कारोबार का अध्ययन

(पृष्ठ –1 से आगे; दिनवार विवरण)

प्रतिनिधिमंडल ऑर्गेनिक मांड्या, बैंगलोर में

प्रतिनिधिमंडल ने पहले दिन 15 जुलाई, 2025 को ऑर्गेनिक मांड्या, बैंगलोर का दौरा किया, जो जैविक कृषि और किसान सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला एक अनुकरणीय संगठन है।

इस यात्रा के दौरान, ऑर्गेनिक मांड्या के प्रतिनिधियों ने सह-संस्थापक और सीईओ सुश्री सहाना हाइडा द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से अब तक की ऑर्गेनिक मांड्या की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताया। प्रतिनिधिमंडल ने ऑर्गेनिक मांड्या के पैकेजिंग और प्रसंस्करण सुविधा केंद्र का दौरा किया। इसके अतिरिक्त, कृषि उपज के विपणन पर उचित ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रदर्शन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एनएच पर स्थित ऑर्गेनिक मांड्या के रिटेल आउटलेट का भी दौरा किया गया।

इस यात्रा के दौरान, ऑर्गेनिक मांड्या के संस्थापक मधु चंदन के बारे में भी पता चला कि वो एक सफल व्यवसायी हैं, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना आरामदायक जीवन छोड़कर भारत में अपने गृह राज्य कर्नाटक लौट आये और ऑर्गेनिक मांड्या की स्थापना की, जो मांड्या क्षेत्र में किसानों के नेतृत्व में अपनी तरह का पहला जैविक आंदोलन है। अपनी जड़ों की ओर लौटने से पहले के वर्षों में, चंदन ने कुछ परेशान करने वाले रुझान देखे थे जैसे कि कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या में वृद्धि, ग्रामीण आबादी की जीवन प्रत्याशा में कमी, उन्होंने देखा कि पिछले कुछ दशकों में मांड्या में रासायनिक खेती अपनाने से जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों में वृद्धि हुई है। उन्होंने देखा कि किसानों के जीवन में आशा की बहुत कमी आई है - एक ऐसी घटना जो ग्रामीण समुदायों में अब तक अनसुनी थी। उपभोक्ता और किसान व्यवहार को बदलने और किसानों को पारंपरिक तथा अधिक पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चंदन के सफ़र से ऑर्गेनिक मंडया का जन्म हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने ऑर्गेनिक मंडया से मुख्यतः निम्न जानकारी हासिल की:-

* ऑर्गेनिक मंडया रसायन-मुक्त खेती को बढ़ावा देता है और किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने में सहायता करता है।
* उनका खुदरा और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जैविक दालें, मसाले, अचार, घी, बाजरा आदि प्रदान करता है।
* यह उद्यम किसानों के स्वामित्व वाला है और सामुदायिक विकास पर केंद्रित है, जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य के साथ-साथ किसानों की उपज का उचित मूल्य भी सुनिश्चित होता है।
* पारदर्शिता और प्रमाणन के माध्यम से मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, प्रसंस्करण और पैकिंग तथा उपभोक्ता विश्वास निर्माण पर ज़ोर दिया जाता है।

प्रतिनिधिमंडल विग-बास्केट, बैंगलोर में

प्रतिनिधिमंडल 16 जुलाई2025 , को भारत के अग्रणी ऑनलाइन किराना प्लेटफार्मों में से एक, विग बास्केट के बैंगलोर स्थित मुख्यालय का दौरा किया। विग-बास्केट के प्रतिनिधियों ने अपनी वर्तमान प्रगति और भविष्य के दृष्टिकोण को समझाते हुए एक प्रस्तुति दी।

विग-बास्केट एक भारतीय ऑनलाइन किराना स्टोर है, जिसका मुख्यालय बैंगलोर, भारत में है और वर्तमान में टाटा डिजिटल के स्वामित्व में है।

विग बास्केट को 2011 में स्थापित किया था जोकि भारत का पहला ऑनलाइन किराना स्टोर था। यह सुपरमार्केट किराना सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक पंजीकृत कंपनी है। यह भी पता चला कि जनवरी, 2023 तक, कंपनी भारत के30 से अधिक शहरों में काम करती है और प्रति माह लगभग 1.5 करोड़ ऑर्डर प्रोसेसेज करती है।

विग-बास्केट की शुरुआत एक टेक स्टार्ट-अप कंपनी के रूप में हुई थी, जिसकी स्थापना दिसंबर2011 में पाँच उद्यमियों ने की थी, जो 2000 के दशक की शुरुआत में डॉट-कॉम क्रैश से बच गए थे। इस स्टार्ट-अप को शुरू में निजी इक्विटी निवेशक एसेंट कैपिटल द्वारा10 मिलियन डॉलर की पूंजी निवेश के साथ वित्त पोषित किया गया था। 2016 के मध्य तक, विग बास्केट आठ बड़े भारतीय शहरों में काम कर रहा था और भारत का सबसे बड़ा ई-किराना विक्रेता बन गया था। कंपनी का अनूठा विक्रय बिंदु ताज़ा कृषि उपज की डिलीवरी थी, जो हर सुबह स्थानीय बाज़ारों से फल और सब्ज़ियों की खरीद, रेफ्रिजरेटेड गोदामों में भंडारण और दरवाज़े तक ताज़ा सामान पहुँचाने के लिए तापमान नियंत्रित ट्रकों के बेड़े पर आधारित थी। कोविड-19 महामारी के बाद ऑनलाइन किराना खरीदारी की माँग में काफ़ी वृद्धि हुई 2022 की शुरुआत तक, विग बास्केट प्रति माह 70 लाख से ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेस कर रहा था। विग-बास्केट ने पिछले एक-दो वर्षों से हिमाचल प्रदेश से सेब की ख़रीद भी शुरू कर दी है और अन्य सब्ज़ियों सहित हिमाचल प्रदेश से सेब की ख़रीद बढ़ाने की संभावना तलाश रही है। इसके अलावा, विग बास्केट ने मंडी ज़िले के सुंदर नगर के आसपास के कुछ इलाकों से टमाटर की ख़रीद भी शुरू कर दी है।

प्रतिनिधिमंडल ने विग-बास्केट में जो मुख्य बातें समझी, वो निम्नलिखित हैं:

* किसानों और एफपीओ से फलों और सब्जियों की खरीद कैसे की जाती है, जिसमें छंटाई, पैकेजिंग और कोल्ड चेन व्यवस्था शामिल है।
* बिग-बास्केट अपनी मज़बूत तकनीक-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से शहरी उपभोक्ताओं को ताज़ी उपज का दैनिक संग्रह और आपूर्ति कैसे सुनिश्चित करता है।
* बिग-बास्केट का मॉडल तकनीक-संचालित है, जिसमें उपभोक्ता प्रतिक्रिया, समय पर डिलीवरी और गुणवत्ता आश्वासन पर ज़ोर दिया जाता है।
* बिग-बास्केट हिमाचल प्रदेश में सेब की खरीद के लिए काम कर रहा है, जिससे किसानों को सीधे बाज़ारों से जुड़ने में मदद मिली है और बिचौलियों की संख्या घट रही है।

प्रतिनिधिमंडल सह्याद्रि फार्म्स, नासिक में

प्रतिनिधिमंडल 17 जुलाई को एक सफल किसान उत्पादक कंपनी, सह्याद्रि फार्म्स, देखने नासिक, महाराष्ट्र पहुंचा। यह एफपीसी अपनी संपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला के लिए भारत में अग्रणी मॉडलों में से एक के रूप में उभरी है। सह्याद्रि फलों और सब्जियों के लिए भारत का सबसे बड़ा एकीकृत मंच है।

प्रतिनिधिमंडल ने सह्याद्रि फार्म्स एफपीसी की एक नई खाद्य संरक्षण विधि-आईक्यूएफ- IFQ, यूनिट का दौरा किया। इसमें आम की तोतापुरी किस्म के अलग-अलग टुकड़ों को अत्यंत कम तापमान पर तेजी से जमाया जा रहा था।

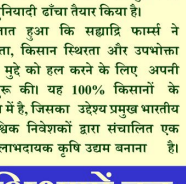

आईक्यूएफ (इंडिविजुअली क्विक फ्रोजेन) एक खाद्य संरक्षण विधि है जिसमें भोजन के अलग-अलग टुकड़ों को अत्यंत कम तापमान पर तेजी से जमाया जाता है। यह बताया गया कि सह्याद्रि फार्म्स की शुरुआत इस मिशन के साथ हुई थी कि भारत के छोटे जोत वाले किसानों को उनकी उपज और श्रम का उचित मुआवजा मिले। एफपीसी ने उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराने की इच्छाशक्ति के साथ कृषि पद्धतियों के वैश्विक मानकों और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा तैयार किया है।

यह ज्ञात हुआ कि सह्याद्रि फार्म्स ने मापनीयता, किसान स्थिरता और उपभोक्ता लाभ के मुद्दे को हल करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। यह 100% किसानों के स्वामित्व में है, जिसका उद्देश्य प्रमुख भारतीय और वैश्विक निवेशकों द्वारा संचालित एक स्थायी, लाभदायक कृषि उद्यम बनाना है। सह्याद्री फार्म्स एफपीसी ने किसानों को समग्र समाधान प्रदान किया है ताकि इस से जुड़े सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती एक लाभप्रद बन सके। सह्याद्री फार्म्स ने अनावश्यक बिचौलियों को हटाकर, बेहतर लॉजिस्टिक्स की पेशकश करके, फसल के बाद के नुकसान को कम करके और उपभोक्ताओं को विश्वास और पारदर्शिता प्रदान करके, एफपीसी ने किसानों के लिए स्थिरता हासिल की है और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता और आश्वासन प्रदान कर रहा है।

किसानों के साथ अपनी अनूठी समावेशी साझेदारी के माध्यम से, एफपीओ ने पिछले कुछ वर्षों में फलों एवं सब्जियों के प्राथमिक प्रसंस्करण, फ्रोजन और एसेप्टिक जैसे अर्ध-प्रसंस्कृत उत्पादों; फलों के जैम जैसे प्रसंस्कृत उत्पादों; टमाटर केचप; फलों के पेय पदार्थों और एक एकीकृत शून्य निर्वहन प्रसंस्करण सुविधा के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण के क्षेत्रों में एक मजबूत क्षमता का निर्माण किया है। सह्याद्री फार्म्स ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में छोटे और सीमांत किसानों के लिए स्थायी आय सुनिश्चित करना संभव बनाया है, जिससे उपभोक्ताओं पर बोझ डाले बिना उनके और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो सके।

* आम प्रसंस्करण इकाई का दौरा किया, जहाँ आमों को जेली, गूदे और अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों में संसाधित किया जाता था। * संगठन सामूहिक प्रयासों के माध्यम से पता लगाने की क्षमता, गुणवत्ता नियंत्रण और बाजार संपर्क सुनिश्चित करता है। एफपीओ से जुड़े किसानों को उच्च रिटर्न, इनपुट आपूर्ति, प्रशिक्षण और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच का लाभ मिलता है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश कृषि मंत्री, प्रो. चंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने 15 से 17 जुलाई तक कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे श्री केवल सिंह पठानिया, उप मुख्य सचेतक, हिमाचल प्रदेश विधानसभा; एचपीसीडीपी, जायका-II से परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान, विषय वाद विशेषज्ञ डॉ. आशीष आनंद, और डॉ. राकेश शर्मा।

हमीरपुर, सोलन की जिला परियोजना इकाइयों ने किया प्रशिक्षणों का आयोजन

कृषि विज्ञान केंद्र, बड़ा में प्रबंधन पर प्रशिक्षण

हमीरपुर: कृषि विज्ञान केंद्र, बड़ा में जिला परियोजना प्रबंधक इकाई, हमीरपुर ने कृषक विकास संघों की प्रबंधन समिति के 43 सदस्यों को एक दिवसीय प्रशिक्षण 29 जुलाई, 2025 को दिलाया।

इस प्रशिक्षण में खंड परियोजना प्रबंधन इकाई ऊना की सिंचाई उप - परियोजनाएं ट्यूबेल सिंचाई योजना इसपुर, ख्वाजा और कन्वर्जेंस योजना के बनोंह और धतवाड़ा- भरेड़ा से कुल 14 लाभार्थियों ने भाग लिया।

खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, हमीरपुर के अंतर्गत आने वाली उप-परियोजनाएं जसोह, कांगड़ी और कन्वर्जेंस योजनाएं सासन, कलूर, कोहला, भगवानी और गरनी-फरनाहट से 25 लाभार्थियों ने भाग लिया। खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, बिलासपुर के अंतर्गत कन्वर्जेंस योजनाओं में शामिल उप-परियोजनाओं से चार लाभार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला परियोजना प्रबंधक श्री डी.डी. शर्मा द्वारा परियोजना के उद्देश्यों के विस्तृत परिचय से हुई। उन्होंने किसानों को परियोजना से अधिकतम लाभ उठाने और संगठनात्मक दक्षता में सुधार लाने हेतु प्रेरित किया।

इस अवसर पर वरिष्ठ सलाहकार श्री बलजीत सिंधू ने किसानों के साथ अपने अनुभव साझा किए और जायका परियोजना चल रहे प्रयासो पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में डा. आर एस ठाकुर ने किसानों को प्रबंधन समितियो की सरचना, कार्य प्रणाली, पारदर्शिता और सामुदायिक सहभागिता के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी।

हमीरपुर के स्वयं सहायता समूह सदस्यों को प्रशिक्षण

मंडी: किसान प्रशिक्षण केंद्र, सुंदरनगर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में स्वयं सहायता समूह के 45 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें से हमीरपुर की 18 और 27 बिलासपुर से 27 सदस्य थीं।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उनके समूह में निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिका और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना था, ताकि वे अपने कार्यों को अधिक प्रभावी और संगठित ढंग से कर सकें। प्रशिक्षण के दौरान पीएमसी से डॉ. पी. एल. शर्मा ने स्वयं सहायता समूह सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की, उन्होंने बताया कि प्रत्येक सदस्य को अपने समूह की प्रगति और पारदर्शिता में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने समूह प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन, बैठक संचालन और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला।

वहीं, श्रीमती रक्षा देवी, शीतला स्वयं सहायता समूह की प्रमुख कार्यकर्त्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार SHGs से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर और सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने समूह चर्चाओं और प्रश्नोत्तर सत्रों में भाग लिया। सभी ने ऐसे प्रशिक्षणों को और अधिक नियमित रूप से आयोजित करने की मांग की।

सोलन के 42 किसानों ने प्रशिक्षण में लिया भाग

सोलन: जिला प्रबंधन इकाई ने एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को विभिन्न कार्यों और दायित्वों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को परियोजना के उद्देश्यों और उनके दायित्वों के बारे में जानकारी प्रदान करना और उन्हें परियोजना में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस एक दिवसीय

प्रशिक्षण कार्यक्रम में 42 किसानों ने भाग लिया, ये सारे किसान खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, सोलन से थे जो विभिन्न उप परियोजनाओं क्षेत्रों से आये थे। खंड परियोजना प्रबंधक डॉ. युवराज ने किसानों को उनके दायित्वों के बारे में जानकारी दी और मासिक बैठकों के आयोजन पर जोर दिया। उन्होंने किसानों से वाटर टैरिफ की वसूली करने और इसका उपयोग भविष्य में कस्टम हायरिंग सेंटर में औजार खरीदने और उन्हें किराये पर किसानों को उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया। विषय वाद विशेषज्ञ डॉ. जितेंद्र ने किसानों को परियोजना की अन्य गतिविधियों के बारे में अवगत कराया और उन्हें परियोजना में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

पहलवान की योजना से 16.75 हे. भूमि सिंचित होगी, 48 परिवारों को मिलेगा लाभ

सरकाघाट: खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, सरकाघाट द्वारा बहाव सिंचाई उप-परियोजना पहलवान का निर्माण करने के लिए ठेका 16 जुलाई को दिया गया। इस अवसर पर हुए विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता श्री पवन ठाकुर ने की। इस कार्यक्रम के दौरान जायका कृषि परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने अपनी विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी साझा की तथा उपस्थित ग्रामीणों से इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। खंड परियोजना प्रबंधक डॉ. अक्षनी कुमार ने कहा कि इस बहाव सिंचाई उपपरियोजना के निर्माण पर लगभग 34 लाख रुपये की लागत आएगी, जिससे लगभग 16.75 हेक्टर भूमि सिंचित होगी और 48 लाभार्थी किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इस से स्थानीय किसानों को वर्ष भर पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे इस सिंचाई सुविधा का उपयोग कर सब्जियों एवं अन्य नकदी फसलों की खेती करें, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत प्रधान काली दास, केवीए पहलवान के प्रधान मनोहर लाल, सचिव रमेश चन्द, कृषि अधिकारी निशांत पराशर, निर्माण अभियंता शशि पाल शर्मा, कनिष्ठ अभियंता सूर्यांश शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सोलन में सिंचाई योजना डमकारी से कनाह का निरीक्षण

सोलन में चल रहे उप-परियोजना प्रवाह सिंचाई कार्य "डमकारी से कनाह योजना" का निरीक्षण पीएमसी और जायका कृषि परियोजना की सांझी टीम ने 18 जुलाई 2025 को किया।

इस निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि निर्माण कार्य दिशा-निर्देशों एवं डीपीआर के अनुसार किया जा रहा है या नहीं। यह निरीक्षण अंकित कुमार (कनिष्ठ अभियंता) डॉ. युवराज (ब्लॉक परियोजना प्रबंधक), गौरव कुमार (निर्माण अभियंता), इं. अश्विनी भारद्वाज (पीएमसी विशेषज्ञ) एवं जीतेन्द्र कुमार (विषय विशेषज्ञ) तथा कृषक विकास संघ के सदस्य श्री रघुवीर की उपस्थिति में किया गया। योजना के अंतर्गत कुल 2,950 मीटर मुख्य चैनल का प्रस्ताव था, जिसमें से अब तक लगभग 1200 मीटर का निर्माण गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है। जलाशयों (टैंकों) की जैकेटिंग के लिए नौ टैंकों का प्रस्ताव था, परंतु कृषक विकास संघ के सुझाव अनुसार दो अतिरिक्त टैंकों की जैकेटिंग भी की गई है, जिससे कुल 11 टैंक जैकेटिंग का कार्य पूर्ण किया गया। साथ ही, डीपीआर अनुसार प्रस्तावित 11 रिटेनिंग वॉल का निर्माण भी पूर्ण रूप से किया जा चुका है। कृषक विकास संघ के सदस्यों को पीएमसी विशेषज्ञ ने सुझाव दिया कि पहले इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता एवं जल-वहन क्षमता की जांच की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जल प्रवाह में कोई बाधा न आए।

लघु किसान को दिया ट्रैक्टर

हमीरपुर: फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में यह सुनिश्चित किया गया कि किसानों को खेतों में मशीनीकरण के माध्यम से लाभ प्राप्त हो, जिससे श्रम शक्ति पर निर्भरता कम हो सके।

रोहविन उप-परियोजना के एक लघु और सीमान्त कृषक को 25 जुलाई 2025 को सोनालिका ट्रैक्टर DI-745 III (HDM) वितरित किया गया जो तहत आने वाले क्षेत्र में आता है। ट्रैक्टर कुल लागत का 50% अनुदान पर प्रदान किया गया।

ट्रैक्टर वितरण के समय उस क्षेत्र के संग्रहण केंद्र के प्रभारी विस्तार अधिकारियों द्वारा लाभार्थी किसान को यंत्र के सर्वोत्तम उपयोग के बारे में मार्ग दर्शन प्रदान किया गया तथा यह भी समझाया गया कि इस प्रकार के मशीनीकरण से क्षेत्र में फसल विविधीकरण को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अंत में, लाभार्थी किसान ने परियोजना के हस्तक्षेपों से प्राप्त हो रहे लाभों के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और अधिकारियों को उनके मार्ग दर्शन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2, जायका-ओडीए, के स्वामित्व में परियोजना भवन, कृषि परिसर, हमीरपुर-177001 से, परियोजना निदेशक डॉ सुनील चौहान द्वारा संपादित, प्रकाशित एवं मुद्रित। संपर्क: 01972-223059; iechplicaagriculture9@gmail.com